साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 26 फरवरी-03 मार्च 2024 वर्ष-9, अंक-45
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

राज्यसभा में पेश केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश में जैविक खेती का एक चौथाई रकबा

भोपाल। जागत गांव हमार

खादों के ज्यादा उपयोग से जमीन और मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट के बीच अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ा है। देश में जैविक खेती का सबसे बड़ा रकबा मध्य प्रदेश में 15 लाख 92 हजार हेक्टेयर है। दूसरे नंबर पर 13 लाख हेक्टेयर के साथ महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात में नौ लाख 37 हजार हेक्टेयर, राजस्थान में छह लाख 78 हजार है। बाकी राज्यों में जैविक खेती का रकबा तीन लाख हेक्टेयर से कम है। देश में कुल 64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। केंद्र सरकार की पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में तीन हजार से अधिक क्लस्टर बने हैं। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की पिछले दिनों राज्य सभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।

- देश में कुल 64 लाख हेक्टे. क्षेत्र में जैविक खेती
- कृषि विकास के अंतर्गत प्रदेश में तीन हजार से अधिक क्लस्टर बने
- सरकार ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की

जैविक कृषि नीति बनाई | मध्य प्रदेश सरकार ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश में खेती का कुल रकबा डेढ़ करोड़ हेक्टेयर है। प्रदेश में कुछ किसान लंबे समय से जैविक खेती करते रहें हैं, पर सरकारी प्रोत्साहन के साथ इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में प्रत्येक विकासखंड में एक गांव में जैविक खेती के साथ हुई थी। केंद्र सरकार की जैविक उत्पादन कृषि नीति के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई है।

प्रोत्साहन का प्रावधान

जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उत्पादों का सीधे विक्रय की जगह ब्रांड नाम उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, जैविक उत्पाद विपणन केंद्रो का विकास, प्रसंस्करण की सुविधाएं प्रदान करना, उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण शामिल है।

15 लाख टन जैविक उत्पाद

किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 14 से 15 लाख टन जैविक उत्पाद तैयार हो रहा है। इसमें लगभग पांच लाख टन से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। सहकारिता के माध्यम से भी इसे और विस्तार दिया जा रहा है।

एडवांस्ड मिल्कोमीटर से 35 तरह की होगी जांच

तीन मिनट में मिलेगी रिपोर्ट, 40 नई लैब आ रहीं

अब हर जिले में होगी दुग्ध जांच की चलित प्रयोगशाला

भोपाल। जागत गांव हमार

बाजार में बिकने वाला दूध शुद्ध है या नही, इसकी जांच करने के लिए प्रदेश के हर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग के पास एडवांस्ड मिल्कोमीटर होगा। इस उपकरण को अगले माह के पहले सप्ताह में प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराए जाने की योजना है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। दरअसल, अभी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में खाद्य चलित प्रयोगशाला की सौगात दी गई है, जिसमें पुराने मिल्कोमीटर लगे हैं। अब इनको नए एडवांस्ड मिल्कोमीटर से अपडेट किया जाएगा। वहीं प्रदेश में आने वाली 40 नवीन चलित प्रयोगशालाओं में पहले से एडवांस्ड मिल्कोमीटर लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुरानी चलित प्रयोगशालाओं में लगे मिल्कोमीटर में चार-पांच जांच ही हो पाती थी। अब एडवांस्ड उपकरण से दूध से जुड़ी 35 तरह की जांच आसानी से हो सकेंगी। इतना ही नहीं, दुग्ध जांच की रिपोर्ट भी दो-तीन मिनट में मिल जाएगी।

तीन माह पहले दिया था प्रशिक्षण

दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारियों को तीन माह पहले मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। विशेषज्ञों की मानें तो दूध की जांच करने की मशीन जिले में उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्तर पर जांच कर कार्रवाई करने में आसानी होगी। सैंपल की प्राथमिक जांच में गड़बड़ी मिलने पर त्वरित कार्रवाई भी की जा सकेगी।

जांच में नहीं लगेगा समय 15 वाहन होंगे अपडेट

इधर,खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे का कहना है कि नए उपकरण आने से दूध और अन्य खाद्य सामाग्री की आसानी से जांच हो सकेगी। अभी नमूनों को जांच के लिए तैयार करने में समय लगता है। जो सैंपल तैयार कर मशीन में रखेंगे, उसकी रिपोर्ट करीब 3 मिनट में पूरी होगी। प्रदेश में अभी 15 चलित खाद्य प्रयोगशाला हैं। अभी जो मिल्कोमीटर हैं, उसमें 4 से 5 तरह की जांच होती है। जबकि एडवांस्ड मशीन में 35 तरह की जांच होगी। वहीं आने वाली 40 नई चलित प्रयोगशालाओं में यह मिल्कोमीटर अपडेट वाला ही लगा है। इसके साथ ही पहले से चल रहे 15 वाहनों में इसे अपडेट किया जाएगा। वर्तमान में हर प्रयोगशाला तीन से पांच जिलों में जाकर जांचें कर रही है।

प्रदेश के किसानों से 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदेगी सरकार

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जाना है, जिससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड से समन्वय कर उपार्जन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वैस्ट जोन) दलजीत सिंह तथा महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले से समत्व भवन में सौजन्य भेंट के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी केन्द्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की पुष्टि के लिए विशेषज्ञ, नमी मापक यंत्र, बारदाना सहित अन्य आवश्यक उपकरण की उपलब्धता और किसानों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश से अतिशेष गेहूं का परिदान लेकर कमी वाले राज्यों को भेजने की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण से चर्चा में कहा कि प्रदेश

अहम फैसला: दाह संस्कार के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा

सरकार ने गौशालाओं को बनाएगी आत्मनिर्भर

में गौ-माता के सम्मान के लिए शीघ्र ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। डॉ. यादव ने कहा कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गौ-माता के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आती हैं। कई बार गौ-माता इन दुर्घटनाओं का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौ-माता सड़कों पर न दिखें और उन्हें गौशालाओं अथवा सुरक्षित स्थानों में स्थान मिले। इसके अलावा गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गौ-माता के सम्मान में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती है तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था होना चाहिए। इस संबंध में ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का दायित्व निर्धारित किया जाएगा। गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हों इसके लिए समाधि अथवा उनके दाह संस्कार के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा का मेजें थपथपाकर स्वागत किया। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी इस कार्य में लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशु पालन एवं डेयरी विभाग को इस संबंध में आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए ताकि वर्षाकाल के पूर्व व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें।

बैठक बुलाने के निर्देश

पशु पालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वे शीघ्र ही गौशाला संचालकों को बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशु पालन विभाग द्वारा इसी माह यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरों के महापौर और निकायों से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल किए जाएं। बैठक में गौ-शालाओं के बेहतर संचालन, गौ-पालकों द्वारा गौ-माता के स्वतंत्र विचरण पर अंकुश, पुलिस द्वारा सहयोग प्राप्त करने और केंद्र सरकार से इस संबंध में अधो संरचनात्मक कार्यों के लिए राशि प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा कर दी बधाई

प्रदेश में सिर्फ 29 दिनों में तैयार हुआ देश का पहला जन-मन आवास

मप्र में बना देश का पहला जन-मन आवास

शिवपुरी। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को जन मन योजना के तहत एक लाख से अधिक आवास स्वीकृत कर हितग्राहियों को राशि जारी की थी। इसके बाद महज 29 दिनों में मप्र के शिवपुरी जनपद के कलोथरा गांव में भागचंद्र आदिवासी का जन-मन आवास बनकर तैयार हो गया। देश के 28 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेशों के 1.60 लाख स्वीकृत आवासों में बनकर तैयार होने वाला यह देश का पहला आवास है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि हर गरीब का अपना पक्का आवास हो। इस संकल्प की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। भागचंद्र आदिवासी को पीएम जनमन आवास अंतर्गत दो लाख रुपए आवास की सामग्री के लिए, 19,890 रुपए मनरेगा मजदूरी के रूप में एवं 12 हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए, कुल 2,31,890 रुपए प्रदान किए गए थे। आवास तैयार होने के बाद भागचंद्र आदिवासी ने कहा कि पहले जब पानी बरसता था तो बिना पन्नी (पालीथिन) के गुजारा नहीं होता था। बहुत बार तो आटा अनाज सब भीग जाता था। बहुत ज्यादा परेशानी आती थी। यहां तक कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे। जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरा पक्का मकान बन जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे मकान बनाकर दिया है। भागचंद्र ने बताया कि अधिकारियों से पता चला कि पूरे देश में मेरा पहला मकान बना है। इस घर को बनाने में मेरी पत्नी रामकुंवर आदिवासी के साथ दोनों लड़के भी दिनरात मेहनत करते रहे और अब हमारा सपना साकार हो गया है।

हर दिन अधिकारियों ने की मॉनिटरिंग

मध्यप्रदेश के आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह हर दिन फोटो मंगवा कर योजना मॉनिटरिंग करते थे। अधिकारियों ने नियमित मॉनिटरिंग की और इसके परिणाम स्वरूप 29 दिनों में आवास बनकर तैयार हुआ। जिले में 12 हजार सहरिया आदिवासियों के लिए आवास स्वीकृत हुए हैं।

- भागचंद्र आदिवासी को 15 जनवरी को राशि जारी की गई थी। इसके बाद घर बनाने के लिए शासन के निर्देशानुसार समय पर नींव डालने, आवास साग्रमी कम दर पर क्रय करने से लेकर घर बनाने तक में पंचायत के इंजीनियर और अधिकारियों ने मदद की। ग्राम पंचायत की ओर से कारीगरों की उपलब्धता कराई गई।

गिर्राज शर्मा, सीईओ,जनपद, शिवपुरी

मध्यप्रदेश में एक्सपोर्ट की कमी आए सामने

फसल का उठाव नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान

दाम नहीं मिलने से राजगढ़ के संतरा उत्पादक किसान परेशान

सारंगपुर। जागत गांव हमार

फसल का उठाव नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। व्यापारी अधिक दाम लेकर फसल खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि खेती में किसानों की लागत बढ़ गई है। खेती की बढ़ी हुई लागत के कारण किसान परेशान है। सारंगपुर क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसान इन दिनों अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित है। किसानों का कहना है कि पहले ही बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढने से वहां पर संतरा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के व्यापारी संतरे की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। सारंगपुर क्षेत्र में संतरे की खेती अधिक होती है। यहां से पूरे देश में संतरे का एक्सपोर्ट होता है पर इस साल यहां के किसानों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। यहां पर किसानों को 20 रुपए से अधिक की कीमत नहीं मिल रही है। जबकि किसानों का कहना है कि व्यापारियों को क्षेत्र के इससे कम दाम में संतरा मिल रहा है। इसलिए व्यापारी यहां के किसानों से फसल की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगताना पड़ रहा है।

संतरे को पेड़ में ही छोड़ रहे हैं किसान

किसानों के संतरे की खरीद नहीं होने के कारण किसान भी अब फलों पर ध्यान नहीं दे रहे है। इसके कारण जनवरी महीने में फसलों की तुड़ाई का मौसम होने के बाद भी किसान अपने पेड़ से फलों की तुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार के प्रतिनिधि संतरे के सरकारी दाम तय करें और किसानों से संतरे की खरीद की जाए, नहीं तो किसानों के संतरे की फसल बर्बाद हो जाएगी और किसानों को नुकसान हो जाएगा।

संतरे की फसल के कमजोर दाम

डॉ. अंकित यादव ने बताया कि संतरा एक ऐसा फल है जो दुनिया भर के लोगों की पसंद बनी हुई है। संतरा न जाने कितने पोषकीय तत्वों और रोग निवारक क्षमताओं से युक्त एक अत्यंत उपयोगी फल है। इस फल की खासियत यह है कि इसका रस शरीर के अंदर पहुंचते ही रक्त में रोग निवारणीय कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिंस जीवनशक्ति प्रदान करने वाले तत्व पचकर शक्तिवर्धन का कार्य करने लगते हैं। इसलिए इसका रस किसी कमजोर व्यक्ति के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

संतरे में मौजूद विटामिन ए

संतरे में पाए जाने वाले पोटेशियम मस्तिष्क में ऑक्सीजन के संचार में सहायता करता है। संतरे में मौजूद विटामिन ए और कैल्शियम के सेवन से हड्डी और दांत के स्वास्थ्य को बढावा मिलता है। आपको बता दे कि इस सीजन में संतरे की बहुत कम डिमांड होने की वजह से भाव बहुत कम हो गए हैं। पिछले साल की तुलना करें तो इस बार 1000 रुपए कम भाव प्रति क्विंटल मिल रहे है। पिछले साल 3200 रुपए क्विंटल का भाव था इस बार मात्र 2200 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है।

पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली

अब चंबल के बीहड़ में भटक गया प्रोग्रेस-वे, किसान करेंगे आंदोलन

मुरैना। जागत गांव हमार

अटल प्रोग्रेस-वे को दूसरे सर्वे के बाद तय किए गए अलाइनमेंट पर बनाने के खिलाफ किसान फिर लामबंद होने लगे हैं। चंबल घाटी किसान एकता संघर्ष समिति की अगुआई में गत दिवस किसान एकजुट हुए और अटल प्रोग्रेस-वे को किसानों की जगह सरकारी जमीनों पर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चंबल घाटी किसान एकता संघर्ष समिति के जिला संयोजक लाखन सिंह सिकरवार की अगुआई में चंबल कॉलोनी पार्क में किसानों के साथ सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार भी थे। समिति के सदस्यों ने कहा, कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे अलाइनमेंट को निरस्त कर नया सर्वे कराने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश सरकार अब उसी अलाइमनेंट पर एक्सप्रेस-वे बनाने पर अड़ी है, जो किसानों के हित में नहीं। इससे हजारों किसान भूमिहीन हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, कि पहले सर्वे में जहां से एक्सप्रेस-वे निकालना तय हुआ था, वहीं से इसका निर्माण हो, नहीं तो चंबल अंचल के किसान आंदोलन को मजबूर होंगे। प्रदर्शन करने वालों में भाजपा नेता उदयवीर सिंह के अलावा भानु प्रताप सिंह, नेमीचंद शर्मा, दिनेश शर्मा, विश्वंभर शर्मा, सुल्तान सिंह, बलवीर सिंह आदि मौजूद थे।

प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने में सिंचाई का सबसे बड़ा योगदान

भोपाल। जागत गांव हमार

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने अपेक्स बैंक सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जल संसाधन विभाग में वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया। मंत्री सिलावट ने कहा कि यह सम्मान वास्तव में प्रदेश में प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने के प्रयासों का सम्मान है। प्रदेश के किसानों को सशक्त करने का सम्मान है। प्रदेश से गरीबी और भूख को खत्म करने का सम्मान है। किसानों के आत्म सम्मान को बढ़ाने का सम्मान है। जल संसाधन विभाग एक परिवार है जो किसानों के लिए काम करता है। उनको सिंचाई के लिए पानी और पेयजल उपलब्ध

कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हमारा लक्ष्य प्रदेश में वर्ष 2025 तक कुल 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है और वर्ष 2047 तक प्रदेश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में पानी पहुंचाना है। हमने प्रदेश में विगत तीन वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर से अधिक नवीन सिंचाई क्षमता विकसित की है। वहीं कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश को 7 वर्षों से लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जल संसाधन विभाग का है। कृषि विभाग और किसानों को आप सब पर गर्व है। आप किसानों को फसल के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

फेस्टिवल-2024: केला निर्यात की बढेंगी संभावनाएं

-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केला उत्पादकों को दी बधाई

बुरहानपुर को 'बनाना' का हब बनाने के लिए सरकार बनाएगी कार्ययोजना

भोपाल। जागत गांव हमार

बुरहानपुर जिले में केला उत्पादन और प्रसंस्करण की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसे बनाना हब बनाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। बुरहानपुर में अनूठे बनाना फेस्टिवल-2024 का शुभारंभ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में केला उत्पादक किसानों, विशेषज्ञों और निर्यातकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रतिभागियों को दिए अपने संदेश में कहा कि बनाना फेस्टीवल के आयोजन से केले से निर्मित विभिन्न उत्पादों की मार्केटिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की प्रक्रियाओं से आमजन को अवगत करवाने से लेकर इस उत्पाद की निर्यात वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री ने उत्सव में विविध गतिविधियों की सराहना की। सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल के तहत एक जिला-एक उत्पाद योजना की शुरुआत से आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में अनेक कदम बढ़ाए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान रचा- सांसद पाटील ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद में बुरहानपुर जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान रचा है। केला फसल के साथ ही हल्दी को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया। महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी यह योजना रोजगार के नये अवसर देकर आर्थिक रुप से इस व्यवसाय से जुडी महिलाओ को सशक्त बना रही है।

16 हजार हेक्टेयर में केला

प्रदेश में सबसे ज्यादा 16 हजार हेक्टेयर में केला फसल का उत्पादन हो रहा है। तीन वर्ष पूर्व हमारे जिले में केला उपज से सिर्फ फल बेचे जाते थे। अब तने से रेशे तैयार कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में जिले ने स्पेशल मेंशन अवॉर्ड में प्रथम राष्ट्रीय पुरुस्कार हासिल कर बुरहानपुर जिले का नाम रोशन किया है।

अपार संभावनाएं

पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। जिले में केले के बाद सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल हल्दी है। केले और हल्दी दोनों ही फसलों की प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की गतिविधियों से इन्हें उगाने वाले किसानों की आय में और वृद्धि होने की अपार संभावनाएं हैं।

उत्पादों को देंगे बढ़ावा

कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि बनाना फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य एक जिला-एक उत्पाद अंतर्गत केले से निर्मित विभिन्न उत्पाद, उनकी मार्केटिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग जैसे अन्य प्रक्रियाओं से अवगत कराना है। बनाना फेस्टिवल में केले एवं हल्दी के प्रसंस्करण में तकनीक, अन्वेषण एवं ब्रिढी पर जोर देना है। भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, केले के रेशे से हस्त शिल्प उत्पाद, केला का रेशा-कपड़ा एवं विविध खाद्य उत्पादों के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मिलेगा रोजगार

विधायक मंजू राजेन्द्र दादू ने कहा कि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए निजी निवेश आमंत्रित करके स्थानीय लोगों को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए केले के फाइबर से टेक्सटॉइल व अन्य वस्तुओं के निर्माण की गतिविधियों का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर करने की आवश्यकता है।

प्रदर्शनी का अवलोकन

अतिथियों ने बनाना फेस्टिवल में आयोजित केले के विभिन्न हस्त शिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा सराहना भी की। वहीं केले से बने व्यंजन को चखकर प्रसन्नता व्यक्त की।

समूह की कहानी अपनी जुबानी

बनाना फेस्टिवल में आजीविका केले से रेशे से निर्मित उत्पाद समूह की कहानी अपनी जुबानी के तहत गौरी स्वयं सहायता समूह शाहपुर उषा उदलकर बताती है कि, समूह की महिलाओं के माध्यम से केले के रेशे से बनाए जा रहे हैं। वे बताती है कि, यूनिट में 6 मशीनों से प्रतिमाह 2500 किलोग्राम रेशा प्राप्त होता है। इस रेशे से दीप, झाड़ू, सौख्यम पेड सहित अन्य उत्पाद बनाये जा रहे है। वे कहती हैं कि 557 महिलायें आत्मनिर्भर बन रही है। इस कार्य से दीदियों को 4 से 5 हजार प्रतिमाह कमा लेती है। फेस्टिवल की श्रृंखला में अतिथियों को फील्ड विजिट भी कराई गई। सुखपुरी स्थित बनाना प्रोसेसिंग यूनिट एवं सामुदायिक भवन दर्यापुर में आयोजित केले के रेशे से निर्मित उत्पादों के संबंध में दिए जा रहे प्रशिक्षण अवलोकन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी के दौरान कहा

पीएम के समृद्ध किसान का पूरा होगा संकल्प नाबार्ड की सराहना और 19 संस्थाएं सम्मानित

भोपाल। जागत गांव हमार

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भोपाल में नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नाबार्ड की टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की समृद्धि का संकल्प दोहराया है उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नाबार्ड, राज्य सरकार और मेहनती किसान मिलकर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देवड़ा ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से आगे बढ़े। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 के लिए नाबार्ड ने 2,58,568 करोड़ का आकलन किया था। कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए 19 संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।

संभाव्यता का आकलन- मप्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्य शासन की पहल पर राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक-नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 2,84,455 करोड रुपए ऋण संभाव्यता का आकलन किया है। यह पिछले साल की तुलना में 9.99 प्रतिशत ज्यादा है। इससे किसानों और छोटे व लघु उद्योगों से जुड़े कामगारों और राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कृषि पर खर्च होगी राशि

संगोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त एसएन मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेखा चंदनावेली मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार संयोजक एसएलबीसी तरसेम सिंह जीरा उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि संभावित ऋण की 63.50 प्रतिशत राशि कृषि क्षेत्र के लिए दी जाएगी जबकि एमएसएमई सेक्टर के लिए 31.50 प्रतिशत और शेष शिक्षा, आवास, नवकरणीय ऊर्जा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च होगी।

इन पर फोकस

मुख्य रूप से फसल उत्पादन, विपणन संधारण, जल संसाधन, कृषि मशीनीकरण, उद्यानिकी, सेरीकल्चर, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि अधोसरचना खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण, सूक्ष्म ऋण और वित्तीय समावेश जैसे क्षेत्रों के लिए दी जाएगी।

11,022 करोड की ऋण संभावना आंकी

जल संसाधनों के संवर्धन और विस्तार के लिए 11,022 करोड की ऋण संभावना आंकी गई है। कृषि मशीनीकरण के लिए 15,977 करोड़, उद्यानिकी क्षेत्र के लिए 5,477 करोड़, वानिकी और जल संग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए 676 करोड़, पशुपालन के लिए 15,318 करोड़, मछली पालन के लिए 935 करोड़, कृषि अधोसरचना के लिए 4,405 करोड़ खाद्य एवं कृषि संस्करण के लिए 7,430 करोड़ और एमएसएमई के लिए 89,471 करोड नवकरणीय ऊर्जा के लिए 796 करोड़ रुपए की ऋण की संभावना आंकी गई है।

सेक्टर	करोड़	फीसदी
कृषि ऋण	1,57,571	55
एमएसएमई	89,471	32
कृषि से जुड़े क्षेत्र	15,427	05
प्राथमिकता के क्षेत्र	14,571	05
कृषि अधोसंरचना	7,415	03

सतना में कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ

राज्यमंत्री बागरी ने कहा अन्नदाता हमारा जीवनदाता

भोपाल। जागत गांव हमार

नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों के द्वारा किए गए अथक परिश्रम से ही हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है। किसान हमारा अन्नदाता भी है और जीवनदाता भी। प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाते हुए किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रहे है। राज्यमंत्री सतना में कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ कर समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के हित में लिये गये फैसलों से किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है।

रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ें किसान

राज्यमंत्री ने कहा कि मेले की थीम इम्पावरिंग द फॉर्मर थ्रू नेचुरल आर्गेनिक फॉर्मिंग पर आगे बढ़ते हुए किसान जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाएं और रसायन मुक्त खेती को महत्व दें। प्राकृतिक और जैविक खेती सभी मायनों में हमारे स्वास्थ्य और मृदा स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद हैं। रसायन युक्त खेती के अनेकों दुष्प्रभाव हैं। किसान भी खेती के कामों में तकनीक का अधिकतम उपयोग करें। मोटे अनाजों की खेती को बढ़ाने में किसान सहयोग करें। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। मोटे अनाज के उत्पादों की कीमत पारंपरिक खेती के उत्पादों से ज्यादा होती है। इसका बाहर निर्यात होने से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। प्रधानमंत्री भी मोटे अनाज (मिलेट) की खेती से होने वाले फायदों पर जोर दे रहे हैं।

संघीय मूल्यों की खातिर टालने होंगे टकराव के हालात

वर्ष 2019 के बाद जब से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी है, केंद्र सरकार और गैर-भाजपा शासित राज्यों के बीच टकराव बढ़ गए हैं। विशेष रूप से तीन राज्य इस संघर्ष के केंद्र में रहे हैं-पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। सभी मामलों में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करते प्रतीत होते हैं। इन राज्यों का दावा है कि केंद्र ने उन्हें उनके राज्य का पैसा देने से इंकार कर दिया है, उनके राज्य की सांस्कृतिक विरासत की उपेक्षा की है आदि। हाल के महीनों में दो अन्य राज्य असहमतों के इस क्लब में शामिल हो गए हैं। ये हैं- पंजाब और कर्नाटक, जहां क्रमशः आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। पंजाब के राज्यपाल वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ भिड़ गए।

जहां तक कर्नाटक की बात है, पिछले मई में जब से कांग्रेस सत्ता में लौटी है, उसकी सरकार का केंद्र से कई बार टकराव हो चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मोदी सरकार पर राजस्व के संबंध में कर्नाटक के खिलाफ भेदभाव करने और सूखे से प्रभावित किसानों की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहने का आरोप लगाया है। हाल ही में सिद्धारमैया और शिवकुमार ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर एक विरोध बैठक आयोजित कर अपना मामला राष्ट्रीय राजधानी में उठाया। कुछ दिनों बाद केरल के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य कीओर से इसी तरह के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पंजाब में कुल मिलाकर 30 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। वे भारत की आबादी के पांचवें हिस्से से अधिक हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लैंगिक समानता के मामले में केरल और तमिलनाडु देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से हैं। तमिलनाडु एक औद्योगिक ऊर्जा केंद्र भी है। कर्नाटक लंबे समय से वैज्ञानिक शोध के मामले में अग्रणी रहा है और हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तब बंगाल के कुछ सबसे बहादुर लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आजादी के बाद से इस राज्य ने हमें कुछ बेहतरीन संगीतकार, फिल्म निर्माता और विद्वान दिए हैं। पंजाब के सिखों ने हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे सशस्त्र बलों में आनुपातिक रूप से भारत के किसी भी अन्य समुदाय की तुलना में कहीं अधिक योगदान किया है। पांच राज्य, जिनमें से प्रत्येक का हमारे देश के अतीत एवं वर्तमान में विविध और विशिष्ट योगदान है तथा प्रत्येक राज्य में भाजपा से भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं, क्या राज्यों एवं संघ के बीच चल रहा मौजूदा विवाद वास्तव में हमारे देश के हित में है? इससे पहले कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दूं, हाल

ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की कुछ टिप्पणियों पर ध्यान दें, जिनमें उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को संसद में लगातार तीसरी बार बहुमत न मिले। फरवरी की शुरुआत में अपने राज्य के अंतरिम बजट के दौरान रेड्डी ने कहा कि अगर केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी अपने अस्तित्व के लिए दूसरों दलों पर निर्भर रहती है तो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की बेहतर संभावना होगी। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन या पिनरई विजयन के विपरीत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी भी नरेंद्र मोदी, भाजपा या केंद्र सरकार के प्रति टकराव का रुख नहीं अपनाया। लेकिन अब वह भी गैर-भाजपा शासित राज्य सरकारों के प्रति मोदी सरकार के अहंकारी, दबंग और वास्तव में सत्तावादी रवैये को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि क्या जगन रेड्डी की धीरे-धीरे आलोचनात्मक मुद्रा और अधिक उग्र विरोध में तब्दील हो जाएगी या क्या तेलंगाना के नए कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक में अपने पार्टी सहयोगियों के साथ मिलकर केंद्र से अधिक कर राजस्व और निष्पक्ष व्यवहार की मांग करेंगे। भले ही ये दोनों मुख्यमंत्री अलग रहें, लेकिन भाजपा के प्रभुत्व वाली केंद्र सरकार और गैर-भाजपा शासित राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब के बीच चल रहा टकराव बेहद चिंताजनक है, जो मुझे पहले पूछे गए प्रश्न पर वापस लाता है। इन टकरावों के कहां तक जाने की संभावना है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के कथनी और करनी को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा किसी भी आधार पर इन राज्यों की मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहती। इनके तीन तरीके हैं, जिनसे यह अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों के हितों और इच्छाओं के खिलाफ खुद को और भी मजबूती से स्थापित करना चाहती है। पहला है, अपनी एड़ी-चोटी का जोर लगाना, और विपक्ष द्वारा नियंत्रित राज्यों को संसाधनों से वंचित करने और उनके स्वायत्त कामकाज पर और अधिक अंकुश लगाने के लिए उन शक्तियों का उपयोग करना, जिन्हें केंद्र ने कोविड महामारी के बाद से हड़प लिया था। दूसरा, नागरिकों से अगले विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों के बजाय भाजपा को वोट देने के लिए कहना, इन राज्यों के निवासियों से वादा करना कि यदि वे 'डबल इंजन सरकार' चुनते हैं तो उनके साथ अधिक अनुकूल व्यवहार किया जाएगा। तीसरा है, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके अन्य दलों के विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना।

आयोग के गठन से रोजगारपरक समस्याओं के समाधान की उम्मीद

किसी पूर्व सैनिक को 12 बोर के लाइसेंस के लिए तहसीलों के चक्कर काटते, थाने के कारिंदों की चिरौरी करते देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन्होंने टैंक, तोपें, मिसाइलें चलाई हैं, कमांडो ऑपरेशन किए हैं, वे कचहरी के बाबुओं के सामने असहाय हो रहे हैं। यहां सिफारिश की संस्कृति चलती है, लेकिन नया रिटायर होकर आया पूर्व सैनिक कुछ करना चाहे, तो मुश्किलें रास्ता रोकती हैं। अब तो तीन वर्ष बाद अग्निवीर भी सैन्य सेवा से वापस आने लगेंगे। पिछले हफ्ते संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने सीमा पर बलिदान हुए अग्निवीरों के लिए सरकार को सुझाव दिया है कि उनके परिवार को नियमित सैनिकों की तरह पेंशन फंड दी जाए। उन्हें भी देश/प्रदेश की सेवाओं में समायोजन के आश्वासन दिए गए हैं। यदि यह व्यवस्था अभी से नहीं बनाई गई, तो अचानक सारी व्यवस्थाएं करने में मुश्किलें आ सकती हैं।

लगभग प्रत्येक राज्य की सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी में पांच फीसदी से 15 फीसदी तक आरक्षण की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण पांच फीसदी है। जातीय एजेंडे की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा में पूर्व सैनिकों के आरक्षण को जातीय कोटे में बांट दिया है। अब तक जो सैनिक बिना जातीय आरक्षण के सेना में रहे, उन्हें अब राज्य सरकार की सेवाओं में समायोजन के लिए अपनी जाति बतानी पड़ रही है, जाति-प्रमाणपत्र लेना पड़ रहा है। इन संशोधनों के चलते पहले से चला आ रहा चयन बाधित हो गया है। दूसरी ओर, व्यवस्थागत कमियों के कारण तृतीय श्रेणी में आरक्षण कोटे का पूरी तरह भरा जाना संभव नहीं हो पाता। हालांकि योगी सरकार में स्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समरूप नीतिगत दखल की आवश्यकता है। उधर हथियारों के लाइसेंस मिलने में भी अलग-अलग राज्यों में समस्याएं हैं। नतीजतन सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलने में भी मुश्किलें हो जाती हैं। प्रत्येक पूर्व सैनिक को पेंशन फंड की तरह एक शस्त्र के लाइसेंस का अधिकार भी सेवानिवृत्ति लाभ की तरह दिया जाना चाहिए। पूर्व सैनिकों के पास शस्त्र होने से उनके गांव या मुहल्लों, जहां वे रहते हैं, के नागरिकों को सुरक्षा का आभास होता है। पूर्व सैनिक प्रशिक्षित मानव शक्ति हैं, जो सिविल में पुलिस, सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग, वायरलेस ऑपरेशन, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा आदि विभागों में कई दायित्वों को बखूबी निभा सकते हैं। उनके आने से विभागीय कार्यक्षमताओं में वृद्धि ही होगी। नगर प्रबंधन, ग्राम स्तरीय योजनाओं के संचालन, शिक्षा व्यवस्था आदि में उनकी सक्रिय भागीदारी हो सकती है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय में वह प्रशासनिक शक्ति नहीं है, जिसके तहत वे विभिन्न विभागों से आरक्षित कोटे के भरे जाने के संबंध में प्रगति विवरण मांग सकें। पूर्व सैनिकों के रोजगार, स्थानीय समस्याओं यथा भूमि-विवादों संबंधी विषयों का भी त्वरित समाधान होता नहीं देखा गया है। आधारभूत समस्या यह है कि पूर्व सैनिकों के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्रालय न होने के कारण न तो उच्च स्तरीय समीक्षाएं हो पाती हैं, और न ही विभिन्न विभागों में रिक्तियों की स्थिति का पता चल पाता है। नतीजतन समस्याओं के समाधान के नीतिगत रास्ते नहीं बन पाते। उदाहरण के लिए, पुलिस, वन विभाग, होमगार्ड, शिक्षा आदि कई विभागों में नियुक्तियों केअवसर आते रहते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों के विषयों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल पाती, क्योंकि पूर्व सैनिक संवर्ग समाज कल्याण मंत्रालय का एक बहुत छोटा भाग होता है। राज्यों में भी पूर्व सैनिकों का कोई अलग मंत्रालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण के लिए एक राज्यमंत्री तो होता है, लेकिन अलग विभाग व अलग सचिव न होने से उनकी प्रभावशीलता अत्यंत सीमित हो जाती है। कोई आत्मनिर्भर सचिव व सक्षम प्रशासनिक संरचना के न होने के कारण सैनिक कल्याण मंत्री का पद दिखावटी होकर रह गया है। यदि महिला आयोग, अजाज आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह राज्यों में एक पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाए, तो नीतिगत, व्यवस्थागत और रोजगारपरक समस्याओं के समाधान के रास्ते निकल सकते हैं।

केंद्रीय चुनावी बॉन्ड योजना अब पारदर्शिता आएगी

सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2017 में पेश की गई चुनावी बॉन्ड योजना को हाल ही में रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने यह भी माना कि असीमित कॉरपोरेट फंडिंग की अनुमति देने वाली कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) के प्रावधान को हटाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत पेश करता है। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से कहा है कि 12 अप्रैल, 2019 तक की गई ऐसी सभी खरीद का विवरण आगामी छह मार्च तक चुनाव आयोग को दें। साथ ही चुनाव आयोग को एसबीआई से मिली सभी जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक प्रकाशित करना होगा। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कोई व्यक्ति या संगठन उन्हें खरीद सकता है और अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान कर सकता है। ये दल उन्हें 15 दिन के बाद भुना सकते हैं। इन बॉन्डों को खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए सख्त केवाईसी मानदंड हैं। खरीदारों की पहचान एसबीआई को होती है, जिसके पास इसके लेन-देन का एक समर्पित विंग है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह थी कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और कंपनी अधिनियम के तहत राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता के उद्देश्य को विफल करती है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के अभाव में चुनावी बॉन्ड योजना के खत्म हो जाने पर पारदर्शिता आने के बजाय राजनीतिक फंडिंग के और अधिक अपारदर्शी हो जाने की आशंका है। दरअसल, कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक दल को बड़ा चंदा नहीं देना चाहेगी, और विशेष रूप से खुलेआम ऐसा करते हुए दिखना भी नहीं चाहेगी। इसकी वजह यह नहीं है कि कॉरपोरेट फंडिंग किसी भी तरह से भ्रष्ट या अवैध है, बल्कि यह है कि कोई खास व्यक्ति या कंपनी किसी खास राजनीतिक दल को इसलिए पसंद करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आर्थिक नीतियां एवं विचार अन्य दलों से बेहतर हैं। लेकिन इस व्याख्या को या तो अस्वीकार्य माना जाता है या छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि पहले इस तरह के राजनीतिक चंदे गुप्त रूप से या अधिकांशतः भ्रष्ट तरीके से दिए जाते थे। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक चंदे के उन अनियमित साधनों को खत्म करने के लिए एक सुधारात्मक योजना थी। बॉन्ड नकद नहीं खरीदे जा सकते थे और उनकी खरीद के लिए सख्त केवाईसी मानदंडों की आवश्यकता थी। यह एक मिथक है कि भारतीय लोकतंत्र छोटे दान से जीवित रह सकता है।

-बीमारियों ने भी फसल को घेरा, किसानों की बढ़ गई चिंता

मंदसौर में अफीम की फसल में लग रहा रोग, काले पड़ रहे डोडे

मंदसौर। जागत गांव हमार

मंदसौर जिले में अफीम फसल में अभी किसान चीरा लगा रहे हैं। इस समय अफीम को बीमारियों ने भी घेर लिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है की अफीम में काली, सफेद मस्सी का रोग गया है, इसके कारण डोडों का रंग काला होने लगा है, अफीम का पौधा भी सूखने लगा है। काली-सफेद मस्सी के कारण अफीम उत्पादन प्रभावित होने की बात भी किसान कह रहे हैं।

अफीम के पट्टे मिलने के बाद किसान खेती कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में अफीम की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। अफीम के पौधों में आने वाले डोडों से अफीम निकालने का काम किया जा रहा है। किसान और परिजन खेतों में डोडों की चिराई और लुनाई के काम में जुटे हैं। वर्तमान में जिले में मौसम में खासा परिवर्तन हो रहा है। सुबह-शाम जिले में सर्दी का प्रकोप है, जबकि दोपहर के समय सर्द हवाओं के साथ गर्मी का मौसम भी असर दिखा रहा है। मौसम के इस बदलाव से जिले में अफीम की फसल में रोग आ रहे हैं। किसानों की मानें तो अफीम के पौधों में काली और सफेद मस्सी का प्रकोप है।

किसान हो रहे परेशान

रोग से प्रभावित हो रही फसल को देख किसान चिंतित है। जिले में इस वर्ष तीनों खंडों में नियमिति एवं सीपीएस के पट्टे मिलाकर लगभग 17 हजार से अधिक किसानों को 10-10 आरी के पट्टे दिए गए हैं। बोवनी के बाद अनुकूल मौसम से अफीम फसल प्रारंभ में बेहतर रही। बाद में दिसंबर माह में बादल छाए और बूंदाबांदी भी हुई।

अफीम की फसल प्रभावित

पूरे सीजन में मौसम अफीम के लिए अनुकूल ही रहा। फरवरी माह में किसान अफीम डोडों में चीरा लगा रहे हैं। इस दौरान मौसम में हुए बदलाव का असर अफीम की फसल पर पड़ रहा है। अफीम में काली व सफेद मस्सी का प्रकोप बढ़ा है। इसके कारण अफीम के उत्पादन पर असर होगा। किसानों का कहना है की बीमारी के कारण उत्पादन प्रभावित होगा तो औसत भी पूरी नहीं हो सकेगी।

काली मस्सी| काली मस्सी के प्रभाव से अफीम का डोडा काला पड़ जाता है। समय के साथ यह डोडा सूख जाता है। इससे अफीम की प्राप्ति नहीं होती है।

सफेद मस्सी| सफेद मस्सी का रोग लगने से अफीम का पौधा जड़ से लेकर डोडे तक पूरी तरह सूख जाता है। डोडों के सूखने से अफीम का उत्पादन नाम मात्र का भी नहीं होता है।

किसानों की पड़ा

- अफीम फसल में काली व सफेद मस्सी का प्रकोप है। इसके कारण डोडे काले पड़ रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं। इस बीमारी के कारण अफीम का उत्पादन भी प्रभावित होगा।

- शोभाराम
किसान, मंदसौर

- मौसम परिवर्तन होने के कारण अफीम फसल पर काली व सफेद मस्सी का प्रकोप होने से फसल प्रभावित हो रही है। इसके कारण उत्पादन भी प्रभावित होगा। अफीम के साथ ही अन्य सभी फसलों में भी नुकसान है।

- दिनेश, किसान नोगांवा

वेटरनरी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च को बैठक में होना था शामिल

जिम्मेदार अधिकारी इन दिनों शोध से ज्यादा निजी कार्यों को महत्व दे रहे

गाय पर शोध करने दिल्ली में मंथन अवकाश पर गए डायरेक्टर रिसर्च

जबलपुर। जागत गांव हमार

वेटरनरी विश्वविद्यालय में शोध कार्य संभाले वाले डायरेक्टर रिसर्च विभाग इन दिनों अपनी जिम्मेदारियों से ही पीछे हट गया है। विभाग और इसके जिम्मेदारी अधिकारी इन दिनों शोध से ज्यादा निजी कार्यों को महत्व दे रहे हैं। उनकी इस कार्यशैली की वजह से विवि के हाथ से कई प्रोजेक्ट जा सकते हैं। हालात यह है कि विवि को प्रोजेक्ट और बजट देने वाली एजेंसियों के साथ होने वाली बैठक में भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वेटरनरी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च विभाग में सामने आया है।

हाथ से जाएगा 12 करोड़ का प्रोजेक्ट - राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गाय की प्रजातियों के संवर्धन से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में विश्वविद्यालय के साथ बैठक है। इसमें विवि डायरेक्टर रिसर्च विभाग के मुखिया डॉ. एसएस तोमर और उनकी टीम को शामिल होना है, लेकिन वे अचानक अवकाश पर चले गए हैं। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर बैठक आयोजित कर रहे एनिमल हस्बैंडरी एंड डेयरी गर्वमेंट आफ इंडिया के आला अधिकारी उनसे संपर्क करते रहे, लेकिन हो नहीं पाया। जानकारी की माने तो बैठक में शामिल न होने से विवि के हाथ से 12 करोड़ का यह प्रोजेक्ट जा सकता है।

शोध के कार्य भी कर दिया नजरअंदाज

विवि प्रशासन भी उनके बैठक में न जाने से परेशान है। इधर दिल्ली की बैठक में विवि द्वारा इस शोध से जुड़े कामों को रखा जाना था। इसके बाद ही यह शोध आगे बढ़ता। इधर डायरेक्टर रिसर्च विभाग के पास मुखिया के अलावा दिल्ली भेजने के लिए कोई दूसरा पशु विज्ञानी भी नहीं हैं। इससे हालात और बिगड़ गए। सूत्रों की माने तो डायरेक्टर रिसर्च विभाग के मुखिया ने कुछ माह पूर्व ही यह जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन प्रोजेक्ट के प्रति उनकी सजगता के बाद अब विवि द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इधर सूत्रों की मानें तो विश्वविद्यालय के कुलपति चयन की प्रक्रिया इन दिनों अंतिम पड़ाव पर है। इस वजह से विवि की ओर से आवेदन करने वाले उम्मीदवार, कार्य की बजाए चयन प्रक्रिया में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं।

26 किसानों से छल करने पर दोषी को 26 बार पांच-पांच साल का कारावास

बड़वानी। छल-कपट से 26 किसानों से फसल प्राप्त कर भुगतान नहीं करने के दोषी अभिषेक पुत्र राजेश गुप्ता निवासी बजरंग कालोनी राजपुर को न्यायालय से 26 बार पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 2.60 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट रईस खान ने सुनाया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान ने की। उन्होंने बताया कि मामला 23 मार्च 2021 से 26 मार्च 2021 का है। अभियुक्त अभिषेक और उसके पिता राजेश ने किसानों के घर-घर जाकर उनसे उनकी मक्का कपास खरीदी और भुगतान नहीं किया। फसल के विक्रय मूल्य का भुगतान नहीं कर इसके लिए पांच जून 2021 को शपथ पत्र पर झूठी लिखा-पढ़ी की जाकर फरियादी और अन्य किसानों के साथ छल किया। फरियादी राकेश की रिपोर्ट पर थाना ठीकरी में आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट सहायक उपनिरीक्षक निलेश गड़बड़ी द्वारा लेख की जाकर, प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अभियुक्त राजेश फरार है।

लहसुन की चोरी से बचने के लिए तैनात करना पड़ा बंदूकधारी, नीलगायों का झुंड गेहूं के खेतों में जाकर फसल को नुकसान पहुंचा रही

आसमान पर लहसुन के भाव, बंदूक लेकर पहरेदारी कर रहे किसान

उज्जैन। जागत गांव हमार

इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लहसुन, गेहूं की उपज तैयार होने जा रही है, लेकिन ग्रामीण नील गाय एवं चोरी से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि लहसुन को उखाड़कर चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नीलगायों का झुंड गेहूं के खेतों में जाकर फसल को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में सुरक्षा के लिए किसानों को बंदूकधारियों को तैनात करना पड़ रहा है। मंगरोला के किसान जीवन सिंह ने बताया कि उसके दो बीघा के खेत में लहसुन को उखाड़ कर तैयार कर रहे हैं। ऐसे में रात को चोरी से बचने के लिए बंदूकधारी जवानों को तैनात करना पड़ रहा है। बता दें इन दिनों लहसुन काफी महंगी बिक रही है। एक सप्ताह पहले 40 हजार रुपए क्विंटल तक बिक गई थी। लेकिन इन दिनों 12 से 15 हजार रुपये क्विंटल बिक रही है।

सीसीटीवी से भी रखवाली

महंगी लहसुन को बचाने के लिए बंदूकधारियों के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी रखवाली की जा रही है। भारत सिंह बैस ने बताया कि जिले में नीलगायों का काफी जमावड़ा हो गया है, वह देर रात में गेहूं के खेतों में घुसकर फसल में नुकसान पहुंचा रही है। उनसे फसल को बचाने लिए भी रात में सुरक्षा जरूरी हो गई है। इसलिए किसानों ने बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों को खेतों की निगरानी में लगा रखा है।

अभी जांच दल के रिकॉर्ड में सिर्फ नौ गांव में नुकसान

25 फीसदी से कम नुकसान पर नहीं मिलेगा मुआवजा

ओले ने बर्बाद कर दी छतरपुर के गांवों में किसानों की फसल

छतरपुर। जागत गांव हमार

खेतों में लहलहाती फसलें देख किसान रोमांचित थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। करीब एक या दो महीने का इंतजार था और फसल पककर किसानों के घरों तक पहुंचती। लेकिन फरवरी महीना ऐसा मौसमी बदलाव लेकर आया कि किसानों की उम्मीदों पर ओलों ने पानी फेर दिया। वह खड़ी सरसों, गेहूं और चना की फसलों पर बरस पड़े। खेतों में खड़ी फसल आंखों के सामने बर्बाद हो गई। कहीं मटर तो कहीं बेर के आकार के ओले खेतों में बरसे। बारीगढ़, चंदला, लवकुशनगर, नौगांव, हरपालपुर क्षेत्र के दर्जनों गांवों में ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो गईं। नुकसान के बाद सर्वे करने पहुंची राजस्व विभाग की टीमों ने कुछ गांवों में नुकसान पाया। मूल्यांकन टीम के अधिकारियों ने अभी करीब नौगांवों में बड़ा नुकसान पाया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर 25 फीसदी से कम नुकसान पाया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन खेतों में 25 फीसदी से कम नुकसान हुआ है वह मुआवजे के दायरे से बाहर रहेगा। जहां 25 फीसदी से ज्यादा नुकसान पाया जाएगा उसे नुकसान की श्रेणी में रखा जाएगा। अभी नुकसान के सर्वे का कार्य जारी है।

यहां किसानों पर टूटा कहर- कितने गांवों में कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन सर्वे पूरा होने के बाद ही किया जा सकेगा। इन गांवों में गिरे थे ओले, जमींदोज हो गई थीं फसलें पिछले सप्ताह छतरपुर जिले के बारीगढ़ गौरिहार क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी। जहां बेर के आकार में गिरे ओलों ने फसलों को बर्बाद कर दिया था। जहां घूर, बरैया, सिंचारी, गौरिहार, चंदला विधानसभा क्षेत्र के मुंडेरी, बेड़ी, शाहपुर, बेहटा, रामुपुरा, लवकुश नगर क्षेत्र में थुराठी, देवनगर, बम्हौरी, नाहरपुर आदि गांवों में ओलावृष्टि हुई थी।

मंत्री भी देख चुके बर्बादी

जहां कुछ गांवों में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार खुद नुकसान को देखने के लिए पहुंचे थे और किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था। हरपालपुर क्षेत्र में यहां किया जाएगा नुकसान का सर्वे हरपालपुर क्षेत्र के गांवों में गलान, लहदरा, मडोरी, नाऊपहारिया, रानीपुरा, कैमहा, कराठा, सरसेड आदि गांवों में नुकसान पहुंचा है। जहां टीम नुकसान का सर्वे करेगी। हालांकि ग्रामीणों ने बड़े स्तर पर नुकसान की बात कही है। किसानों ने बताया है कि बेर के आकार के ओलों से फसल बेकार हो गई है। इनका कहना है जो ओलावृष्टि हुई है उससे कुछ गांवों में नुकसान हुआ है।

- अभी हमारे सर्वे में करीब नौगांव ऐसे हैं जहां बड़ा नुकसान पाया गया है। अन्य जगहों का सर्वे चल रहा है। जहां 25 फीसदी से कम नुकसान पाया जाएगा वह नुकसान के दायरे में नहीं आएगा।

- आदित्य, सोनकिया, एसएलआर, जिला छतरपुर

प्रदेश में पहली गणना में 10 हजार से ज्यादा गिद्ध मिले

चीता, बाघ, घड़ियाल, तेंदुआ ही नहीं गिद्ध स्टेट भी एमपी!

भोपाल। मध्य प्रदेश के चीता, बाघ, घड़ियाल, तेंदुआ के बाद अब गिद्धों की संख्या में भी देश में अव्वल रहने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश में 2024 की गिद्ध गणना 16 से 18 फरवरी तक हुई। इसमें प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा संख्या में गिद्ध होना पाया गया। हालांकि, अभी यह अंतिम आंकड़ा नहीं है। प्रथम चरण में की गई गणना में अभी कई जगह से आंकड़े मिले नहीं हैं। ऐसे में अप्रैल 2024 में प्रदेश में गिद्धों की संख्या को लेकर अंतिम आंकड़े जारी किए जाएंगे। हालांकि, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले 2021 में भी सबसे ज्यादा गिद्ध प्रदेश में ही पाए गए थे। 2021 में 9446 गिद्ध गणना में मिले थे। दूसरे कई राज्य गिद्धों की गणना नहीं कराते हैं, हालांकि पिछली बार तमिलनाडु और गुजरात ने गिद्धों की गणना कराई थी। जिसमें तमिलनाडु में पांच हजार और गुजरात में चार हजार गिद्ध पाए गए थे।

गिद्धों की संख्या बढ़ने की वजह

प्रदेश में 2019 में गिद्धों की संख्या 7906 थी। यहां गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन विभाग और वन्य प्राणी संस्थान ने संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी सात टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्यों समेत 33 जिलों के 900 से अधिक स्थानों पर गिद्धों की गणना की थी। इसमें हर जगह गिद्धों की संख्या बढ़ी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए गिद्धों की संख्या बढ़ रही है। प्रोटेक्टेड एरिया प्रदेश में टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण अधिक है।

गिद्ध पर्यावरण के मित्र

गिद्ध मृत बड़े जानवरों को ही खाते हैं। इससे वे संक्रमित बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानकारी के अनुसार 1990 के आसपास देश में गिद्धों की संख्या चार करोड़ के आसपास थी, जो लगातार घटती गई। भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से चार विलुप्तप्राय हैं।

धान और गेहूं की खेती में ज्यादा लगता है पानी

आमदनी के लिए किसान कर रहे वीएनआर अमरूद की खेती

भोपाल। केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उद्यानिकी फसलों को लगाने के लिए कर रही है प्रोत्साहित। इसके बढ़ते महत्व को देखते हुए कई किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी कर रहे हैं। ऐसे ही भिंड जिले के विकासखंड अटेर के ग्राम ऐंतहार के प्रगतिशील किसान डीपी शर्मा हैं। उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी शुरू की और वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। किसान डीपी शर्मा ने बताया कि कृषि विज्ञान केन्द्र और उद्यानिकी विभाग से परामर्श लेकर उन्होंने वीएनआर अमरूद का बगीचा लगाया, जिसमें 550 पौधे अमरूद, 50 पौधे नींबू, 100 पौधे करौंदा और 11 पौधे कटहल के थे। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग भिण्ड की तरफ से उनके बगीचे में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवाया गया है। ड्रिप के माध्यम से सभी पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी और खाद दिया जा रहा है। वर्तमान में इन पौधों में फल आने लगे हैं, जिसमें एक फल लगभग 400 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक का अमरूद का उत्पादन होने लगा है।

रिसर्च के लिए इंदौर आई टीम, अब किसान ही तय करेंगे दाम

मध्यप्रदेश की फसलें और जड़ी बूटियां जाएंगी यूरोप

इंदौर। जागत गांव हमार

मप्र की फसलें और जड़ी बूटियां यूरोप के देशों में जाएंगी। यूरोपिय देशों के लोग मप्र के किसानों से सीधे यह उत्पाद खरीद सकेंगे। किसान इन उत्पादों पर अपने दाम भी तय कर सकेंगे। यह बात नीदरलैंड्स से आए डॉ. आर तिवारी ने एक खास बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि साल 2017 से उनकी टीम मप्र में रिसर्च कर रही है। यहां के मिलेट्स, जड़ी बूटियां और फसलें यूरोपिय देशों में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। यह एक आनलाइन कंपनी होगी जो मप्र के किसानों और यूरोप के लोगों को सीधे जोड़ेगी। किसान खुद अपने प्रोडक्ट्स का दाम तय कर सकेंगे।

रसायनिक खेती से बढ़ रही बीमारियां- तिवारी ने बताया कि यूरोप समेत दुनिया के कई देश रसायनिक खेती से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि रसायनिक खेती की वजह से बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। जैविक उत्पादों की डिमांड दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है और इसी के चलते यूरोप भारतीय किसानों के जैविक उत्पाद खरीदना चाहता है।

यूरोप और भारत में होगी जांच

इंदौर का काम देख रही मोनिका यादव ने बताया कि मप्र में बहुत अच्छी खेती होती है। यहां से हम यूरोप के लिए कई फसलें और जड़ी बूटी ले जाएंगे। हल्दी, अदरक, लहसुन, ज्वार, मक्का, बाजरा, आंवला समेत कई चीजें हैं जिन्हें यूरोप के लोग खरीदना चाहेंगे। यह आनलाइन प्लेटफार्म अगले साल लांच हो जाएगा। इसके बाद यूरोप के लोग खुद ही मप्र के किसानों के उत्पाद खरीदकर बुलवा सकेंगे। मोनिका ने बताया कि उत्पादों की जांच भारत के साथ साथ यूरोप में भी होगी और इन सभी चीजों के लिए कंपनी तैयारी कर चुकी है। हम पिछले सात साल से यहां पर इस काम के लिए रिसर्च कर रहे हैं।

दक्षिण अमेरिका के काले आलू की खेती मप्र में हो रही

1 एकड़ में खर्च 50 हजार, मुनाफा 5 लाख रुपए तक, आयरन की कमी भी हो रही दूर

मध्यप्रदेश में अब किसान परंपरागत खेती से हटाकर नई फसलों पर फोकस कर रहे हैं। सागर के युवा किसान दक्षिण अमेरिका में उगने वाले काले आलू की खेती कर रहे हैं। इससे सालाना 5 लाख रुपए तक कमाई हो रही है। काला आलू औषधीय फसल है, जिसके गुण और कीमत सफेद आलू के मुकाबले ज्यादा होती है।

जागत गांव हमार अपने इस अंक में अपने पाठकों को मिलवा रहा है-ग्राम कपूरिया के युवा किसान आकाश चौरसिया से। आकाश ने करीब 15 साल पहले मल्टीलेयर प्राकृतिक जैविक खेती शुरू की थी। अब दूसरे किसान भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। आकाश के पास 16 एकड़ जमीन है। इसमें से एक एकड़ पर काले आलू की फसल लगी है। आकाश ने सागर जिले समेत बुंदेलखंड में पहली बार काले आलू का उत्पादन किया है। उन्होंने एक एकड़ में यह फसल लगाई थी। इसमें करीब 100 क्विंटल पैदावार हुई। वह मध्यप्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के किसानों को काला आलू उगाने की विधि सिखा रहे हैं।

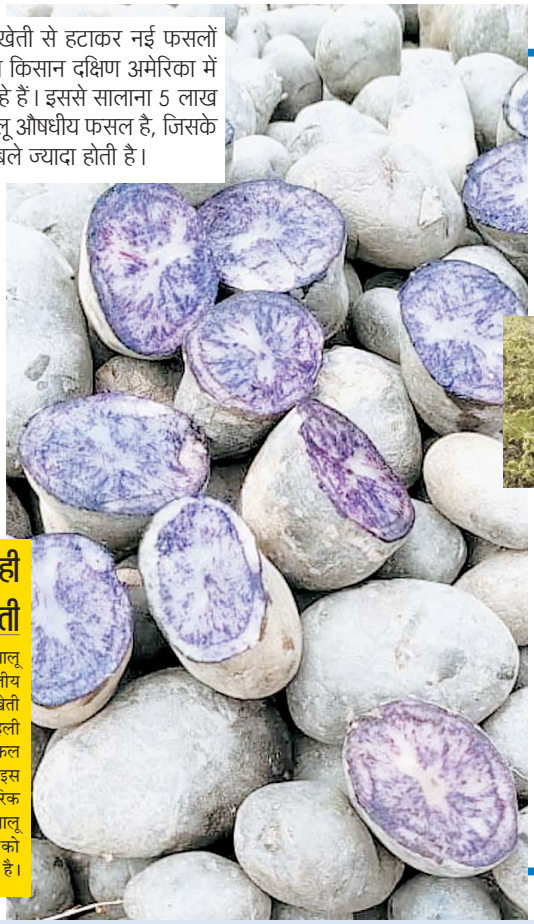

सफेद आलू की तरह ही काले आलू की होती है खेती

आकाश चौरसिया ने बताया कि काले आलू की खेती दक्षिण अमेरिका के एंडिज पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन अब इसकी खेती सागर में शुरू की है। प्रयोग के तौर पर पहली बार काले आलू की खेती की, जो सफल रही। तीन महीने में फसल आ जाती है। इस आलू की ऊपरी सतह काली और आंतरिक भाग गहरे बैंगनी रंग का होता है। काले आलू की खेती करने में एक एकड़ में किसान को करीब 50 हजार रुपए का खर्च आता है।

बोवनी के बाद 90 दिन में तैयार हो जाती है फसल

आकाश बताते हैं कि काले आलू की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बोवनी करने के लिए सबसे

अच्छा समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का होता है। इसमें किसान को खेत की मिट्टी को उपचारित कर बोवनी कर देना चाहिए। बोवनी के बाद करीब 75 से 90 दिन में फसल तैयार हो जाती है। जिसकी खुदाई कर उत्पादन लिया जा सकता है। खेत की तैयारी के लिए गहरी जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लेना चाहिए।

काले आलू की खेती करने का सही तरीका

- काले आलू की बावनी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करें।
- किसान काला आलू लगाने से पहले खेत की जुताई कर तैयार करें।
- काला आलू लगाने के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है।
- 100 किलो चूने का पाउडर और 50 किलो नीम का पाउडर डालकर भूमि को उपचारित करें।
- खेत में 10 टन के हिसाब से प्रति एकड़ गाय का गोबर डालें।
- एक एकड़ में करीब 750 किलो काला आलू के बीज की जरूरत होती है।
- बावनी से पहले बीज को उपचारित करें, ताकि फंगस की बीमारी से बचा जा सकेंगे।
- 15 लीटर पानी में एक किलो चूना डालकर घोल बनाए। उस खोल में बीज को 10 मिनट डालकर रखे। फिर बावनी करें।
- काला आलू लगाते समय बावनी 8-8 इंच दूरी और 2-2 इंच गहराई पर करें।
- हर दस दिन में फसल में सिंचाई करें। पानी का जमाव नहीं होना चाहिए।
- 75 से 90 दिन में फसल पक कर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद खुदाई कराएं।

70 रुपए किलो काला आलू

सफेद आलू की तुलना में काले आलू की कीमत बाजार में अच्छी होती है। बाजार में यह 70 रुपए प्रति किलो और इससे ज्यादा में भी बिकता है। क्योंकि काले आलू में कई औषधीय गुण होते हैं। काला आलू शुगर फ्री होने के साथ ही आयरन से भरपूर होता है। आकाश बताते हैं कि इस आलू का रंग काला होता है। इसे खाने से आयरन की कमी पूरी होती है। खून की कमी वाले मरीजों के लिए यह काफी फायदेमंद होता है।

दो माह में आयरन की कमी दूर

आकाश ने एक खास चर्चा के दौरान बताया कि ब्लैक आलू आयरन रिच के नाम से भी जाना जाता है। काले रंग का आलू, जिसका छिलका काला और अंदर गूदा काले के साथ गहरे बैंगनी रंग का होता है। आयरन की कमी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति यदि लगातार एक से दो महीने तक काले आलू का सेवन करे, तो उसकी आयरन की कमी दूर हो सकती है। इसके अलावा, काला आलू का उपयोग अन्य औषधि के उपयोग में होता है।

मल्टीलेयर पद्धति से खेती

आकाश चौरसिया ने मल्टीलेयर पद्धति से पहली बार खेती कर इस मॉडल को शुरू किया था। मल्टीलेयर पद्धति से खेती कर वह एक साथ चार फसलों का उत्पादन लेते हैं। वे खेत में बांसों की मदद से अस्थाई देशी ग्रीन हाउस तैयार करते हैं। उसके बाद खेत में काली हल्दी की बुआई करते हैं। साथ ही, उसी खेत में पपीता, कुंदरु, ककड़ी, सहजन जैसी फसलों को लगाते हैं। जमीन में कंद वाली फसल लगाकर ऊपर पालक, धनिया व अन्य भाजी लगाते हैं।

पीने के पानी को लेकर आत्मनिर्भर होकर सुकून की जिंदगी जीने लगे

कुल 252 घरों में नल कनेक्शन देकर लोगों की प्यास बुझाई

जल जीवन मिशन से खुश है मेघपुरा के ग्रामीण, मिल रहा पर्याप्त पेयजल

जल से वंचित नहीं रहेगा कोई घर-परिवार, जल जीवन मिशन पहुंचाएगा नल से जल, सबके द्वार

भोपाल। जागत गांव हमार

मेघपुरा नीमच जिले के जावद विकासखंड की गुजरखेड़ी सांखला ग्राम पंचायत का गांव है जो गंभीर नदी के तट पर बसा है। मेघपुरा में 252 परिवार जनसंख्या 1185 हैं, मेघपुरा विकासखंड मुख्यालय जावद से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। मेघपुरा वासियों के सामने पीने के पानी को लेकर बड़ी चुनौती थी। पीने का पानी दूर स्थित खेत के कुओं से लाना पड़ता था। पुरुष वर्ग साईकिलों पर डिब्बे बांधकर पानी लाते थे। वहीं महिलाएं भी पानी के लिए बड़ा संघर्ष करती थीं। मगर अब उनके अच्छे दिन आ गए है। यहां नल जल योजना ग्रामीणजनों के लिए वरदान साबित हुई और पीने के पानी को लेकर वे आत्मनिर्भर होकर अब सुकून की जिंदगी जीने लगे हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मेघपुरा में 71. 25 लाख रुपयों की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना बनाई जिसके तहत अगस्त 2021 में कार्य प्रारम्भ करके निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर 252 घरों में नल कनेक्शन देकर लोगों की प्यास बुझाई है। अब ग्रामीणों को नल से शुद्ध जल मिल रहा है। गांव की इंद्राबाई पांडे ने बताया, कि मैं पिछले 40 वर्षों से यहां रह रही हूं। यहां पानी की बड़ी समस्या थीं। दूर- दूर से पानी लाना पड़ता था क्योंकि कुएं या अन्य स्त्रोत गांव से दूर है। इसलिए वहां तक जाना पड़ता था। इसे मजबूरी कहे या जीवन की दिनचर्या का हिस्सा। पानी तो लाना ही पड़ता था। अब हमें आराम मिल गया है।

पानी के साथ ही घरों में ही नहाने-धोने का आराम हो गया

गांव की सुशीला बाई ने पुराने दिनों का स्मरण करते हुए स्थानीय बोली में कहा कि पानी की तो बड़ी परेशानी थीं, माथे पर मटका रखकर पानी लाना पड़ता था। अब हमारे घर में ही पानी मिल रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए टमूबाई कुशवाह, लक्ष्मीबाई कुशवाह ने भी अपने-अपने घरों में नल कनेक्शन लगने से खुशी जाहिर की है। लालीबाई चांदीबाई ने बताया कि अब हमारे जीवन में खुशियां आई और पीने के पानी के साथ ही घरों में ही नहाने-धोने का आराम हो गया है। निर्मला बाई कुशवाह और रोड़ीबाई ने बताया कि पानी की पहले बहुत तकलीफ थी। कुओं-कुओं पर जाना पड़ता था। अब घर में नल है। रोज पानी मिल रहा है।

गांव में 50 हजार लीटर क्षमता की एक उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण किया गया

गांव के ही घनश्याम कुशवाह यहां की पेयजल वितरण व्यवस्था का संचालन करते हैं। समय पर टंकी भरकर नलों के माध्यम से पानी सप्लाय किया जाता है। लोगों को नल जल योजना को लेकर कोई शिकायत नहीं है। लोगों ने नल कनेक्शन की खुशियां मनाई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मेघपुरा में पेयजल स्त्रोत के अंतर्गत एक नवीन नलकूप खनन करवाया। नलकूप से गाँव की योजना बनाई गई। योजना में एक नलकूप और प्रस्तावित है। योजना के तहत गांव में 50 हजार लीटर क्षमता की एक उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण किया गया है। इसी के साथ 20 हजार लीटर क्षमता का एक सम्पवेल भी बनाया है। योजना में 90 एमएम व्यास की 945 मीटर राइजिंग मेन लाइन डाली गई है। इसके अलावा गांव में पानी वितरण के लिए 90 एमएम व्यास की 2400 मीटर एवं 110 एमएम व्यास की 966 मीटर पाइप लाइन डाली गई है।

सोलर एनर्जी प्लांट की योजना बनाने के दिए निर्देश

रेवरा फॉर्म की पूरी जमीन का सीमांकन कराएं: राज्यमंत्री

भोपाल। जागत गांव हमार

नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि सतना जिले में बीज विकास निगम को आवंटित रेवरा फॉर्म की सकल 197 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन कराकर सुरक्षित करें और बीज उत्पादन, फसलोत्पादन में वृद्धि कर आवंटित भूमि का सदुपयोग करायें। उन्होंने रेवरा फॉर्म की 40 एकड़ की नगर निगम के कचरा प्लांट को आवंटित भूमि के अनुपयोगी होने पर वहां सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की संभावनायें तलाशने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री बागरी ने सर्किट हाउस में रेवरा फॉर्म की विकास योजना और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में विद्युत, नल जल योजनाओं की समीक्षा की।

राज्यमंत्री बागरी ने बीज विकास निगम के अधिकारियों को रेवरा फॉर्म में संचालित नर्सरी को और अधिक उपयोगी बनाने तथा रेवरा फॉर्म में उत्पादन बढ़ाकर लाभकारी स्वरूप में लाने के लिये कृषि विज्ञान केंद्र मझगवां के वैज्ञानिकों से भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने रेवरा फॉर्म को उपयोगी बनाए रखने और बीज उत्पादन बढ़ाने के संबंध में प्रयास नहीं करने पर जिला प्रबंधक बीज विकास निगम रामस्वरूप जाटव के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने रेवरा फॉर्म में बीज विकास निगम द्वारा विगत पांच वर्षों में की गई गतिविधियों, खरीफ और रबी सीजन में उत्पादन तथा आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आवंटित 173 हेक्टेयर अर्थात 432 एकड़ भूमि का सीमांकन कराकर फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करें। नगर निगम के अधिकारियों को आवंटित 40 एकड़ की अनुपयोगी भूमि पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने की संभावनायें तलाशकर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए। बताया गया कि रेवरा फॉर्म में आवंटित भूमि का सीमांकन करा लिया गया है।

नगर निगम, विद्युत, जल योजना की समीक्षा हुई

राज्यमंत्री बागरी ने नगर निगम, विद्युत कंपनी और नल-जल योजना, जल जीवन मिशन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग के नवनिर्मित विद्युत सब- स्टेशनों का लोकार्पण कराएं और ट्रिपल आरडीएस के कराये जा रहे कार्यों की सूची उपलब्ध करायें। राज्यमंत्री बागरी ने कहा कि शिवराजपुर के रिक्त बड़े शासकीय भू-खंड और दुर्गापुर के पास रिक्त भू-खंड पर सोलर एनर्जी प्लांट की संभावनायें तलाश कर प्लान बनायें। राज्यमंत्री बागरी ने सीवर लाइन की प्रगति, वैध-अवैध कॉलोनियां एवं स्मार्ट सिटी के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सोहावल, बाबूपुर और सोहौला की नल जल योजना सुचारु रूप से संचालित कर दी गई है। सभी घरों में नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण

राज्यमंत्री बागरी ने जिला चिकित्सालय सतना की स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्य म कक्ष, जन्म-मृत्यु पंजीयन कक्ष, दिव्यांग पंजीयन कक्ष, दवाई वितरण कक्ष, चेस्ट मेडीसिन विभाग, आकस्मिक चिकित्सा, क्षय रोग कक्ष तथा मेडीसिन ओपीडी का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्यमंत्री ने अस्पताल के सर्जिकल वार्ड क्रमांक 1, 2, महिला सर्जिकल वार्ड क्रमांक 5 तथा एसएनसीयू, एएनसी, पीएनसी वार्ड में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं और शौचालय की साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही सोनोग्राफी कक्ष का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं।

मोहन सरकार ने मंत्री विजय शाह का ही वेयर हाउस कर दिया ब्लैक लिस्टेड

प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की कार्रवाई, अब 176 गोदामों पर लगा ताला

भोपाल। भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश के 176 वेयरहाउस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इनमें खंडवा जिले के दो वेयर हाउस शामिल हैं। इनमें जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के परिवार का गोदाम भी है। यह प्रतिबंध मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नई गाइड लाइन व प्रावधान किए गए हैं। इसमें खरीदी के लिए निर्धारित पात्रता धारक गोदाम को ही खाद्य निगम द्वारा इस वर्ष खरीदी वह भंडारण की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा की गई जांच में सामने आया कि खाद्यान्न उठाव के दौरान कई समस्याएं सामने आती हैं। इससे कार्य प्रभावित होता है। इनमें समय पर गोदाम नहीं खुलना एप्रोच रोड खराब होना तौल कांटों की समस्या सहित अन्य परेशानियों को देखते हुए 176 वेयर हाउस को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। जोगीबेड़ा स्थित मंत्री शाह के दिव्य शक्ति वेयर हाउस में तोल कांटे की परेशानी और मां नर्मदा वेयरहाउस में अप्रोच रोड नहीं होने से खाद्य निगम ने दोनों को वर्ष 2020-25 के लिए उपार्जन केंद्र और भंडारण के नहीं बनाए जाने की निर्देश दिए हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)